है, अधिनियम 1957 की धारा 113(1) (क) के अनुसरण में दिल्ली नगर के क्षेत्राधिकार में आने वाली भूमि और भवनों पर सम्पत्ति कर लगता है । निगम ने यह भी सूचित किया है कि सम्पति कर की वसूली तब तक स्थगित नही की जाएगी जब तक जन सुविधाएं उपलब्ध नही करायी जाती है । निगम के अनुसार सम्पति कर निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी भूमि और भवनों पर वसूल किया जाता है । उगाही और सम्पति कर की एकत्रित करने का जन सुविधाओं को उपलब्ध करान या किसी इलाके में उपलब्ध करायी गई सेवाओ से कोई संबंध नही है ।

Appointment of Officials in Civil Defence

2659. SHRI SURAJ BHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some paid posts of Deputy Controllers and Deputy Directors in Civil Defence have been authorised by the Central Government;

(b) if so, under what provisions;

(c) whether it is a fact that officials in the Civil Defence are appointed against their consent by some States in violation of Civil Defence Act 1968; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Yes, Sir.

(b) Under Rule 8 of the Civil Defence Regulations, 1968, the Central Government can declare any appointment or class of appointments in Civil Defence as paid appointments.

(c) and (d). No, Sir. Under sub section (1) of section 5 of the Civil Defence Act, 1968, willingness is envisaged only for purpose of appointment as members of the Civil Defence Corps on application made by the persons. Any member so appointed on voluntary basis can be appointed to such office or command in the Corps as the Controllers deem fit. Government servants who are specifically deputed for whole time or part-time civil defence duties by the Heads of organisations or services concerned and officials appointed to paid posts are governed by the conditions of service prescribed by the State Government concerned.

Setting up of Heavy Water Plants

2660. SHRI R. P. GAEKWAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set up two more heavy water plants in the country;

(b) whether the country would be self-reliant on this front with the setting up of the proposed plants; and

(c) if so, the places where the proposed plants are likely to be set up?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) to (c). It is proposed to set up more Heavy Water Plants in the country in order to achieve eventual self-sufficiency in Heavy Water. The exact number and location of Heavy Water Plants to be set up during the Plan period 1980-85 are yet to be decided.

H.A.L. to manufacture Short-hop Aircraft

2661. SHRI K. KUNHAMBU: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Hindustan Aeronautics Ltd. has entered into collaboration with foreign firms for the manufacture of short-hop Aircrafts; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI C. P. N. SINGH): (a) and (b). Presumably the Honourable Member, by the words "short-hop aircrafts" is referring to a small passenger aircraft to

man the proposed third level feeder air services in the country. If so, Hindustan Aeronautics Limited have not entered into collaboration for the manufacture of such aircrafts with any foreign firms.

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए बैंक ऋणों में अड़चन

2662. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जातियों को व्यापार और उद्योग के सिलसिले में उनकी जरूरतें पूरी करने के लिये दिये जाने वाले बैंक ऋण पर ब्याज और शेयर पूंजी में रियायत प्रदान करने की सुविधा के संबंध मे अड़चन पैदा हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने मे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने प्रस्तावित हुए है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) और (ख). उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को अपने कार्यक्रम मे उद्योग और व्यापार की कुछ योजनाएं है, इनको संस्थागत वित्त के साथ जोड़ा जाता है और निगम सामान्यतः अतिरिक्त धन राशि ऋण निवेश उपलब्ध करता है। फिर भी निगम द्वारा सहायता को अनुमादित पद्धति के अधीन इसका अतिरिक्त धनराशि ऋण सामान्यतः 6000 – रुपये तक की कुल लागत की गैर-आवर्ती योजना के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियो के बहुत से परिवारो जो गरीबी रेखा मे नीचे है और जो किसी अन्य स्रोत से सहायता प्राप्त नही कर सकते, को इसके अन्तर्गत लाना है। यदि कोई योजना अथवा 6,000/-रुपये से अधिक की लागत की गैर-आवर्ती योजनाओ की कोई श्रेणी उपयुक्त पाई जाती है तो निगम द्वारा उनको शुरू किये जाने से पहले भारत सरकार का पूर्व अनुमादन प्राप्त करना होगा। इस सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम से एक पत्र प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार का यह सुझाव दिया गया है कि बड़े परिव्ययों को उद्योगों के लिए योजनाओं के सम्बन्ध में प्रत्येक क्षेत्रीय विभाग द्वारा तैयार की जा रही अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाया जाय, विशेष कर निगम राज्य वित्त निगम, लघु उद्योग निगम, राज्य हथकरघा निगम आदि जैसी एजेंसियों से वित्त का प्रबन्ध कर सकता है। आवेदकों और मामले में कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित कर कें वे अपेक्षित सहायता प्राप्त करें। व्यापार के संबंध में योजनाओं के लिए कोई कठिनाई न हो क्योंकि गैर-आवर्ती लागत अनिवार्य रूप से निर्धारित अधिकतम सीमा में होगी। उत्तर प्रदेश सरकार और निगम ने उसके बाद आगे कोई पत्र नहीं लिखा अथवा न ही किसी बाधा को सूचित किया।

Bus Chassis

2663. SHRI T. R. SHAMANNA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether has come to the notice of Government that there is considerable difficulty to get chassis for providing buses to the growing needs and also for the replacement of old and unserviceable buses for the Karnataka State Road Transport Corporation;

(b) whether Government would enquire as to why the manufacturers are not manufacturing more and more buses; and

(c) whether the Central Government would take necessary steps to arrange for providing more chassis very badly needed by the Karnataka State Road Transport Corporation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) The Association of State Road Transport Undertakings has reported that the request of the Karnataka State Road Transport Corporation for 532 Telco chassis and 402 Leyland chassis was pending delivery as on 31st March, 1980.

(b) and (c). Government has requested the manufacturers to accord due priority to the supply of bus chassis to State Road Transport Undertakings. The manufacturers have been requested to meet the needs of Karnataka State Road Transport Corporation during the current year in full.